

अध्याय III: अनुपालन मामले

3.1 प्रस्तावना

अधिनियम औषधि क्षेत्र के निर्धारितियों सहित निर्धारितियों को खर्च अनुमतियों/कटौतियों की स्वीकार्यता निर्धारित करता है। आन्तरिक अनुसंधान एवं विकास (आरएण्डडी) केन्द्रों के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) द्वारा जारी (मई 2014) मार्गनिर्देशों के अनुसार सचिव, डीएसआईआर को अधिनियम की धारा 35 (2एबी) के प्रयोजनों हेतु प्रधान अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। प्रधान अधिकारी अधिनियम द्वारा निर्धारित फार्म 3 सीएम/3 सीएल में आरएण्डडी व्यय अनुमोदित करता है। निर्धारितियों के दावे की प्रामाणिकता अभिनिश्चित करने में एओज़ की सहायता करने के लिए डीएसआईआर से डीजीआईटी (छूट) को फार्म 3 सीएल में आरएण्डडी व्यय का अनुमोदन भेजने की अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) तथा राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) जैसे नियामक निकाय हैं जो समय समय पर औषधि क्षेत्र से सम्बन्धित खर्चों जैसे फ्रीबीज , उपहारों पर खर्च, चिकित्सक नमूना आदि को विनियमित करने के लिए निर्देश/मार्ग निर्देश जारी करते हैं।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने अनुपालन मामला निम्नवत पाया:

तालिका 3.1 कर प्रभावों के साथ अनुपालन मामले

विषय	मामले	(₹ करोड़ में)
		कर प्रभाव
खण्ड क: डीएसआईआर तथा एमसीआई और एनपीपीए जैसे निकायों द्वारा जारी निर्देशों/मार्गनिर्देशों के अनुपालन में औषधि क्षेत्र से सम्बन्धित अस्वीकार्य खर्च	36	55.10
खण्ड ख: औषधि क्षेत्र में अनुपालन मामले	171	714.24
जोड़	207	769.34

खण्ड क

औषधि क्षेत्र से सम्बन्धित अस्वीकार्य खर्च

हमने खर्चों की अनुमति से सम्बन्धित 7 राज्यों¹² में ₹ 55.10 करोड़ के कर प्रभाव वाले 36 मामले देखे जहाँ एओज द्वारा नियामक निकायों के निर्देशों/मार्गनिर्देशों का पालन नहीं किया गया था। इन मामलों में नियामक निकायों द्वारा इन्हें अनियमित किए जाने अथवा कारोबार से असम्बन्धित किए जाने के बावजूद औषधि क्षेत्र में कम्पनियों द्वारा चिकित्सा व्यवसायियों को उपहारों, फ्रीबीज तथा चिकित्सक नमूना के प्रति व्यय एओज ने अस्वीकृत नहीं किया अथवा आंशिक रूप से अस्वीकृत किया। तालिका 3.2 निर्धारण में गलतियों की श्रेणियों का सार और उनका कर प्रभाव दर्शाती है। इन मामलों के ब्यौरे इस अध्याय में दिए गए हैं।

तालिका 3.2 कर प्रभाव के साथ गलतियों का स्वरूप

गलतियों का स्वरूप और प्रतिवेदन का पैरा संख्या	मामले	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
1. चिकित्सा पेशेवरों को उपहारों तथा अन्य फ्रीबीज पर व्यय की अनुमति (पैरा 3.1.1)	21	45.43
2. बिक्री प्रोत्साहन खर्चों से न लिए गए फ्रीबीज/उपहारों पर खर्च का बयौरा (पैरा 3.1.2)	11	-
3. चिकित्सा नमूने पर खर्च (पैरा 3.1.3)	3	1.57
4. राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा शास्ति (पैरा 3.1.4)	1	8.10
जोड़	36	55.10

अधिनियम, भारतीय चिकित्सा परिषद, सीबीडीटी/न्यायिक उदघोषणा द्वारा अनियमित बनाए जाने के बावजूद एओज ने उपहारों, यात्रा सुविधाओं, मेजबानी, नकदी अथवा आर्थिक अनुदान पर व्यय अनुमत किया।

3.1.1 चिकित्सा व्यवसायियों को उपहारों, फ्रीबीज आदि के प्रति व्यय की अनुमति

अधिनियम की धारा 37(1) की व्याख्या के अनुसार प्रयोजन, जो एक अपराध है अथवा जो कानून द्वारा प्रतिबन्धित है, के लिए कोई खर्च स्वीकार्य कारोबार व्यय नहीं है। एमसीआई ने अपने 2002 के विनियमों¹³ के तहत प्रावधान किया

¹² आंध्रप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, तमिलनाडु तथा उत्तराखण्ड

¹³ भारतीय चिकित्सा तथा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार तथा आचारशास्त्र) विनियम 2002

कि जहाँ तक सम्भव हो चिकित्सक जैविक दवाईयां लिखें। यह अन्य के साथ विज्ञापन प्रयोजन हेतु किसी औषधि अथवा दवाई किसी अनुमोदन अथवा सिफारिश के लिए अथवा किसी रोगी को किसी मेडिकल, सर्जिकल अथवा अन्य निदान का निर्देश देने अथवा सिफारिश करने के लिए कोई कमीशन, उपहार आदि मांगने अथवा प्राप्त करने से उन्हें प्रतिबन्धित करता है। संशोधन दिनांक 10 दिसम्बर 2009 के द्वारा औषधि कम्पनियां विशेष रूप से उपहार, यात्रा सुविधाएं मेजबानी, नकदी अथवा आर्थिक अनुदान आदि के स्वरूप में कोई इनाम देने से प्रतिबंधित की गई थीं। सीबीडीटी ने 2012 में एक परिपत्र¹⁴ जारी किया और स्पष्ट किया कि ऐसे खर्च स्वीकार्य नहीं होंगे। न्यायिक उदघोषणा¹⁵ ने भी स्पष्ट किया कि यह परिपत्र पूर्वव्यापी प्रभाव रखता था।

हमने 5 राज्यों¹⁶ में 21 मामले देखे जिनमें एओ ने ऐसे खर्च अनुमत किए थे जो डाक्टरों को दिए गए फ्रीबीज के स्वरूप के थे जिनमें ₹ 45.43 करोड़ का कर प्रभाव निहित था (देखें बॉक्स 3.1)

बॉक्स 3.1 फ्रीबीज खर्च पर गैर/आंशिक अस्वीकृति के निदर्शी मामले	
क. प्रभार	: सीआईटी VII। मुम्बई
निर्धारिती	: मैकलिओड्स फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2009-10
पैन	: AAACM4100C

हमने देखा कि एओ ने 9 दिसम्बर 2009 से 31 मार्च 2010 तक की अवधि से संबंधित चिकित्सकों को उपहारों, फ्रीबीज आदि पर खर्च ₹ 58.71 करोड़ में से केवल ₹ 21.75 करोड़ (यह मानकर कि ऐसी अस्वीकृति की प्रभावी तारीख एमसीआई विनियमों में संशोधन की तारीख (अर्थात् 9 दिसम्बर 2009) होगी), अस्वीकृत किए। एओ का आधार उचित नहीं था, क्योंकि कथित संशोधन स्पष्टकारी स्वरूप में था और इसलिए धारा 37 (1) की व्याख्या जो पूर्वव्यापी प्रभाव 01 अप्रैल 1962 से प्रभावी है, के अनुसार अपराध तथा कानून द्वारा प्रतिबन्धित स्वरूप का होने पर ऐसे फ्रीबीज पर खर्च पूर्व वर्षों को भी पूर्णतया अस्वीकृति योग्य थे। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 36.96 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 11.09 करोड़ का सम्भावित कर प्रभाव अन्तर्गस्त है। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

¹⁴ सं. 5/2012 (फा सं. 225/142/2012-आईटीए II) दिनांक 01 अगस्त 2012

¹⁵ कन्फ्रेडरेशन आफ इण्डियन फार्मास्युटिकल्स उद्योग बनाम सीबीडीटी (हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय)

¹⁶ गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, तमिलनाडु

ख. प्रभार	: सीआईटी-IV अहमदाबाद
निर्धारिती	: ट्रोइका फार्मास्युटिकलस लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2010-11
पैन	: AABCT0228K

हमने देखा कि एओ ने डाक्टर और उसकी विवाहिता के यात्रा खर्चों, वितरित उपहार वस्तुओं आदि पर निर्धारिती द्वारा खर्च ₹ 7.48 करोड़ को अनुमत किया जिसके परिणामस्वरूप उतनी ही आय का अवनिर्धारण ₹ 2.54 करोड़ के कर के कम उदग्रहण के साथ हुआ। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

ग. प्रभार	: सीआईटी-एलटीयू, मुम्बई
निर्धारिती	: इपका लेबोरेटरीज लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2009-10
पैन	: AAACI1220M

हमने देखा कि निर्धारिती ने दिल छूने वाले समारोह, डॉक्टरों को प्रयोजिकता तथा कार्पोरेट/ब्राण्ड रीकाल मर्दों पर ₹ 32.91 करोड़ खर्च किया। फ्रीबीज की प्रकृति के होने पर ये खर्च स्वीकार्य नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप उतनी आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 11.09 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त है। उसी प्रभार में एक अन्य निर्धारिती वायथ लिमिटेड (नि. व. 2008-09) के मामले में सीआईटी (ए) ने इस प्रवृत्ति के खर्चों की अस्वीकृतियों को एक तिहाई से पूर्ण ऐसे खर्चों तक बढ़ा दिया है। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

घ. प्रभार	: सीआईटी मध्य बेंगलोर
निर्धारिती	: वास्कुलर कन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2008-09 से 2010-11
पैन	: AAACM8353R

निर्धारिती ने डाक्टर के घरेलू तथा विदेशी यात्रा सहित होटल बुकिंग, उपहारों से संबंधित खर्चों के नि. व. के लिए ₹ 4.73 करोड़, ₹ 6.21 करोड़ तथा ₹ 7.49 करोड़ कुल ₹ 18.43 करोड़ की राशि डेबिट की। फ्रीबीज की प्रकृति के होने पर ये खर्च स्वीकार्य नहीं थे। तथापि एओ ने उन्हें अनुमत किया। इसके परिणामस्वरूप उतनी आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 6.26 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त है। आईटीडी ने कहा (अक्टूबर 2014) की इस मामले में निर्धारण धारा 153 ए के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को का समयबाधित हो रहा है और लेखापरीक्षा आपत्ति को निर्धारण करने के दौरान देखा जाएगा।

ड. प्रभार	: सीआईटी-सैलम, चेन्नई
निर्धारिती	: बी. मोहन कुमार
निर्धारण वर्ष	: 2009-10 से 2011-12
पैन	: AIVPM2483C

निर्धारिती ने रोगियों को दवाईयों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निर्धारती द्वारा स्थापित अस्पताल का दौरा करने वाले डाक्टरों की फीस/व्याख्या के प्रति सम्बन्धित नि.व. के लिए ₹ 2.70 करोड़ ₹ 4.71 करोड़ तथा ₹ 4.94 करोड़ कुल ₹ 12.35 करोड़ की राशि डेबिट की। ये खर्चे कन्फेडरेशन आफ इण्डिया बनाम सीबीडीटी (हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 353 आईटीआर 338 दिनांक 26/12/2012) के मामले में न्यायिक उदघोषणा के मददेनजर स्वीकार्य नहीं थे। तथापि एओ ने उन्हें अनुमत किया। इसके परिणामस्वरूप उतनी आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 4.11 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है।

च. प्रभार	: सीआईटी V, दिल्ली
निर्धारिती	: ओजोन फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2011-12
पैन	: AAACO0056H

हमने देखा कि निर्धारिती ने डाक्टरों के लिए बिक्री प्रोत्साहन सामग्री की खरीद के प्रति ₹ 2.11 करोड़ की राशि डेबिट की है जैसा निर्धारण आदेश में उल्लेख किया गया। फ्रीबीज की प्रकृति के होने के कारण ये खर्चे स्वीकार्य नहीं थे। तथापि एओ ने उन्हें अनुमत किया। इसके परिणामस्वरूप उतनी आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 70.17 लाख का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है।

आईटीडी ने उत्तर में बताया (अगस्त 2014) कि भुगतान चिकित्सा कैम्पों, रक्तदान कैम्पों, वार्षिक पुरस्कार समारोह, बिक्री बढ़ाने के लिए बैठकों के लिए प्रयुक्त छोटी आयुर्वेदिक मर्दों से बनी सामग्री जैसे सोप, फेस वाश जेल्स आदि के लिए किए गए थे।

आईटीडी का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि स्वयं निर्धारण आदेश में वह उल्लेख किया गया था कि निर्धारिती ने अपने उत्तर दिनांक 24 फरवरी 2014 के द्वारा बताया कि डाक्टरों के लिए बिक्री प्रोत्साहन सामग्री के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए ओजोन आयुर्वेदिक से बिक्री प्रोत्साहन उत्पाद खरीदे गए थे जो भारतीय चिकित्सा परिषद विनियम 2002के प्रावधानों का उल्लंघन है।

इस प्रकार एओज ने डाक्टरों को दिए गए फ्रीबीज के प्रति अस्वीकृति में एक समान दृष्टिकोण नहीं अपनाया है और प्रभावी तारीख जिससे ऐसे भुगतान जो कानून के विरुद्ध प्रतिबन्धित है अथवा कारोबार से सम्बन्धित नहीं है, अस्वीकार्य थे, के लिए एक समान व्यवहार नहीं किया है।

एओज ने बिक्री प्रोत्साहन पर व्यय अनुमत किया जिसमें फ्रीबीज पर प्रतिबन्धित खर्च शामिल किए गए

3.1.2 बिक्री प्रोत्साहन खर्चों से न लिए गए फ्रीबीज/उपहारों पर खर्च के ब्यौरे

औषधि कम्पनियाँ चिकित्सकों को फ्रीबीज तथा उपहारों पर नियमित रूप से खर्च करती हैं। इसलिए संवीक्षा निर्धारण कार्रवाइयों के दौरान एओज बिक्री प्रोत्साहन खर्चों के व्यौरे की पूछताछ करते हैं, फ्रीबीज पर खर्चों की पहचान करते हैं और उन्हें अस्वीकृत करते हैं। ऐसा न करने पर ऐसे खर्च बिक्री प्रोत्साहन खर्चों के भाग के रूप में अनुमत किए जाते हैं।

हमने उत्तरांचल तथा महाराष्ट्र में 11 मामले देखे जिनमें एओज ने विस्तृत ब्यौरों की जांच किए बिना बिक्री प्रोत्साहन में शामिल डाक्टरों को दिए गए फ्रीबीज पर खर्च अनुमत किए थे। (देखें बॉक्स 3.2)।

बॉक्स 3.2 बिक्री प्रोत्साहन खर्चों के ब्यौरों की पूछताछ न करने के कारण फ्रीबीज पर खर्चों को अस्वीकृत न करने के निदर्शों मामले

क.	प्रभार	: सीआईटी-एलटीयू, मुम्बई
	निर्धारिती	: ग्लेनमार्क फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड
	निर्धारण वर्ष	: 2009-10 तथा 2010-11
	पैन	: AAACG12207L

निर्धारिती ने नि. व. 2009-10 तथा 2010-11 के लिए क्रमशः ₹ 55.66 करोड़ तथा ₹ 91.96 करोड़ के बिक्री प्रोत्साहन के प्रति खर्च का दावा किया और एओ ने अनुमत किया था। फ्रीबीज पर किए गए खर्च का सत्यापन करने के लिए इन खर्चों के विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध नहीं था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

ख.	प्रभार	: सीआईटी-एलटीयू, मुम्बई
	निर्धारिती	: इपका लेबोरेटरीज़ लिमिटेड
	निर्धारण वर्ष	: 2007-08 तथा 2008-09
	पैन	: AAACI1220M

निर्धारिती ने नि. व. 2007-08 तथा 2008-09 में क्रमशः ₹ 28.64 करोड़ तथा ₹ 41.80 करोड़ के बिक्री तथा विपणन खर्च किए थे परन्तु डाक्टर को प्रदत्त उपहार तथा अन्य फ्रीबीज के खर्चों की पहचान नहीं की गई थी। तथापि नि. व. 2009-10 में हमने देखा कि बिक्री तथा विपणन खर्चों के ₹ 58.95 करोड़ में से ₹ 32.43 करोड़ विभिन्न फ्रीबीज पर खर्च किए थे। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

ग.	प्रभार	: सीआईटी, देहरादून
	निर्धारिती	: सनकेयर फार्मूलेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
	निर्धारण वर्ष	: 2009-10
	पैन	: AAICS9967M

निर्धारिती ने विज्ञापन, और यात्रा एवं वाहन खर्चों के अतिरिक्त विपणन तथा वितरण खर्चों के रूप में पीएण्डएल लेखे में ₹ 30.94 लाख डेबिट किया। निर्धारिती ने तथ्य स्वीकार किया कि कम्पनी की विपणन नीति में डाक्टरों तथा अस्पतालों को नमूनों का वितरण शामिल है तथापि एओ ने उनके ब्यौरे अभिनिश्चित करने के द्वारा उपर्युक्त खर्चमें शामिल फ्रीबीज पर प्रतिबन्धित खर्चों की मात्रा तक अस्वीकृत नहीं किया था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

इस तथ्य के बावजूद कि डाक्टरों को औषधि कम्पनियों द्वारा ऐसे प्रतिबन्धित खर्च उद्योग की नियमित प्रथाएँ हैं, एओज ने बिक्री प्रोत्साहन खर्च शीर्ष के अन्तर्गत ऐसे खर्चों के ब्यौरों की पूछताछ करने के द्वारा फ्रीबीज के खर्चों को अस्वीकृत नहीं किया था।

चिकित्सकों को मुफ्त दिए चिकित्सक नमूनों का खर्च एओज ने अस्वीकृत नहीं किया था।

3.1.3 चिकित्सक नमूनों के प्रति व्यय की अस्वीकृति नहीं/आंशिक अनुमति

चूंकि चिकित्सक नमूने डाक्टरों की मुफ्त दिए जाते हैं और यह जैविक दवाइयों के स्थान पर ब्राण्डेड दवाइयों के पक्ष में दवाइयां लिखने में डाक्टरों का निर्णय प्रभावित करता है इसलिए यह कानूनन अपराध की प्रकृति का था और इसलिए अस्वीकृति योग्य था।

हमने महाराष्ट्र में 3 मामले देखे जिनमें एओ ने डाक्टरों को मुफ्त दिए चिकित्सक नमूनों के खर्चों को अनुमत किया था जिसमें ₹ 1.57 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है (देखें बाक्स 3.3)।

बाक्स 3.3: चिकित्सक नमूनों के खर्चों को अस्वीकृत ना करने के निदर्शी मामले

क.	प्रभार	: सीआईटी- VII, मुम्बई
	निर्धारिती	: सोल्वे फार्मा इण्डिया लिमिटेड
	निर्धारण अधिकारी	: 2008-09
	पैन	: AABCD0322J

निर्धारिती ने डाक्टरों को मुफ्त दिए चिकित्सक नमूनों पर ₹ 2.24 करोड़ खर्च किया जिसे एओ द्वारा अस्वीकृत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप उतनी आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 76.18 लाख का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है।

ख.	प्रभार	:सीआईटी- X, मुम्बई
	निर्धारिती	: फ्लेमिंगो फार्मास्युटीकल्स प्राइवेट लिमिटेड
	निर्धारण वर्ष	: 2009-10 तथा 2010-11
	पैन	: AAACF4211B

निर्धारिती ने डाक्टरों को मुफ्त दिए चिकित्सक नमूनों पर नि.व. 2009-10 तथा 2010-11 के लिए क्रमशः ₹ 1.45 करोड़ तथा ₹ 92.46 लाख खर्च किया जो एओ द्वारा अस्वीकृत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप उतनी आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें क्रमशः ₹ 49.39 लाख तथा ₹ 31.42 लाख का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है। इन मामलों में हमारा तर्क फ्रीबीज के रूप में चिकित्सक नमूनों पर खर्चों को मानना है और इसलिए अस्वीकार्य सीआईटी प्रभार IX मुम्बई में नि.व. 2010-11 के लिए है। उपेन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में सीआईटी (ए) -19 मुम्बई आदेश द्वारा समर्थित था जिसमें यह निर्णीत था कि यद्यपि एमसीआई द्वारा प्रतिबंधित खर्चों की सूची में चिकित्सक नमूना को विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है परन्तु यह केवल फ्रीबीज की प्रकृति में था और इसलिए अस्वीकार्य था। दोनों मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

एओज ने डाक्टरों को मुफ्त आपूर्त चिकित्सक नमूनों के प्रति व्यय अस्वीकृत नहीं किया था जो जैविक दवाइयों के स्थान पर ब्राण्डेड दवाइयों लिखने को उन्हें प्रभावित करते हैं और उनके स्वतंत्र निर्णय को रोकते हैं।

एओज ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उदग्रहीत शास्तियों के प्रति व्यय, जो कानून द्वारा प्रतिबंधित है को अस्वीकृत नहीं किया था।

3.1.4 एनपीपीए द्वारा शास्ति के प्रति व्यय को अस्वीकृत न करना

अधिनियम की धारा 37 की व्याख्या के अनुसार किसी प्रयोजन, जो एक अपराध है अथवा कानून द्वारा प्रतिबंधित है, के लिए निर्धारिती द्वारा किया गया कोई व्यय कारोबार अथवा वृत्ति के प्रयोजन हेतु किया गया व्यय नहीं माना जाएगा और ऐसे व्यय के संबंध में कोई कटौती अथवा अनुमति नहीं की जाएगी। हमने आंध्र प्रदेश में एक मामला देखा जिसमें एओ ने एनपीपीए द्वारा उदग्रहीत शास्ति पर खर्च को अनुमत किया था जिसमें ₹ 8.10 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है (देखें बाक्स 3.4)।

बाक्स 3.4: एनपीपीए द्वारा शास्ति को अस्वीकृत न करने का निदर्शी मामला

प्रभार	: सीआईटी-1, हैदराबाद
निर्धारिती	: डा. रैडडीज लेबोरेटरीज लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2006-07
पैन	: AAACD7999Q

हमने नवम्बर 2011 में देखा कि एओ ने एनपीपीए द्वारा उदग्रहीत शास्ति के प्रति निर्धारिती द्वारा प्रदत्त ₹ 15.43 करोड़ के खर्च को अनुमत किया जो स्वीकार्य नहीं था। आईटीडी ने उत्तर में आरम्भ में आपत्ति को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया (दिसम्बर 2012) कि राशि शास्ति नहीं थी परन्तु अति प्रभार राशि की वसूली थी। तथापि बाद में उपचारी कार्रवाई पूर्ण की गई थी (मार्च 2014) जिसमें सम्पूर्ण दावा यह कहते हुए अस्वीकृत किया गया था कि यह कानून का उल्लंघन है। इसमें उतना अवनिर्धारण के साथ ₹ 8.10 करोड़ के कर के कम उदग्रहण अन्तर्गस्त है। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

खण्ड ख

औषधि क्षेत्र में अनुपालन मामले

3.2 प्रस्तावना

औषधि क्षेत्र में निर्धारितियों के निर्धारण में हमने रियायतों/छूटों /कटौतियों के प्रशासन, निर्धारण की गुणवत्ता, निर्धारण से छूटी आय, स्थानान्तरण मूल्य निर्धारण आदि से सम्बन्धित गलतियां देखीं। वर्तमान अध्याय औषधि क्षेत्र में निर्धारितियों के निर्धारण के दौरान एओज द्वारा अधिनियम के प्रावधानों और सुसंगत नियमों/न्यायिक निर्णयों को लागू करने में कमियों से संबंधित लेखापरीक्षा मामलों से संबंध रखता है। हमने 17 राज्यों¹⁷ में 171 मामलों देखे जहाँ ₹ 714.24 करोड़ के कर प्रभाव के साथ अधिनियम के प्रावधानों का सही प्रकार पालन नहीं किया गया था। तालिका 3.3 निर्धारण में गलतियों की व्यापक श्रेणियों का सार और उनका कर प्रभाव दर्शाती है। इन मामलों के ब्यौरे इस अध्याय में अनुवर्ती पैराग्राफों में दिए गए हैं।

तालिका 3.3 : उनके कर प्रभाव के साथ गलतियों की प्रकृति

गलतियों की प्रकृति और प्रतिवेदन का पैरा संख्या	मामले	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
1. आरण्डडी/सामान्य खर्चों का आवंटन (पैरा 3.2.1)	15	121.21
2. रियायतों/कटौती/छूट/राहत की अनुमति (पैरा 3.2.2)	26	158.89
3. अग्रणीत कारोबार हानि/मूल्यहास का समंजन (पैरा 3.2.3)	28	27.77
4. कारोबार व्यय की अनुमति (पैरा 3.2.4)	22	47.69
5. आरण्डडी खर्चों की अनुमति (पैरा 3.2.5)	14	77.40
6. खर्च अनुमत करने में गलती, जिन पर टीडीएस काटा नहीं गया/जमा नहीं किया गया था (पैरा 3.2.6)	7	5.91
7. निर्धारण में असंगति (पैरा 3.2.7)	3	149.93
8. आय तथा कर की संगणना में गणितीय त्रुटियां (पैरा 3.2.8)	15	14.65
9. विशेष प्रावधान के अन्तर्गत आय का निर्धारण (पैरा 3.2.9)	6	6.11

¹⁷ आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।

10. सामान्य प्रावधान के अन्तर्गत आय का निर्धारण (पैरा 3.2.10)	16	84.21
11. पूंजीगत लाभों का वर्गीकरण तथा संगणना (पैरा 3.2.11)	1	00.74
12. अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन (पैरा 3.2.12)	5	7.58
13. अन्य (पैरा 3.2.13)	13	12.15
जोड़	171	714.24

अनुसंधान एवं विकास तथा सामान्य व्यय या तो वास्तविक आधार पर अथवा उनके बिक्री टर्नओवर अनुपातों के आधार पर लाभार्थी यूनिटों को आवंटित किए जाने अपेक्षित है। एओज ने उन्हें उचित आवंटन अभिनिश्चित किए बिना अनुमत किया।

3.2.1 आरएण्डडी/अन्य सामान्य खर्चों का आवंटन

अधिनियम की धारा 37 सकल लाभ पर पहुंचने के लिए निर्धारिती की आय से कारोबार खर्चों की कटौती का प्रावधान करती है। निर्धारिती की किसी विशेष यूनिट अथवा एक से अधिक यूनिट अथवा सभी यूनिटों को किसी खर्च से उपचित लाभ पर निर्भर विशेष खर्च या तो वास्तविक आधार पर अथवा उनके बिक्री टर्नओवर अनुपातों के आधार पर लाभभोगी यूनिट (टों) को आवंटित किया जाना अपेक्षित है। हमने आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में 15 मामले देखे जिनमें एओज ने उनकी उचित जांच किए बिना सामान्य तथा आरएण्डडी खर्चों का आवंटन अनुमत किया था जिसमें ₹ 121.21 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है (देखें बाक्स 3.5)।

बाक्स 3.5: आरएण्डडी /अन्य सामान्य खर्चों का आवंटन नहीं/आंशिक आवंटन

क. प्रभार	: सीआईटी-एलटीयू, मुम्बई
निर्धारिती	: ग्लेनमार्क जेनरिक लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2009-10
पैन	: AACCG9820D

आरएण्डडी पर खर्चों की भारित कटौती का आवंटन आरएण्डडी की लाभार्थी यूनिटों के बीच बिक्री टर्नओवर अनुपात में किया जाना था। आरएण्डडी पर पूंजीगत तथा राजस्व खर्चों पर ₹ 212.73 करोड़ की कुल भारित कटौती में से गोवा यूनिट को आवंटित (कटौती की पात्र) ₹ 13.13 करोड़ और अन्य यूनिटों (आवंटन के लिए पात्र नहीं) को ₹ 141.27 करोड़ के साथ अधिनियम की धारा 35(2एबी) के अन्तर्गत राजस्व खर्च के संबंध में केवल ₹ 154.40 करोड़ की भारित कटौती निर्धारिती को आवंटित की गई।

तथापि बिक्री टर्नओवर अनुपात के अनुसार ₹ 106.34 करोड़ गोवा यूनिट को आवंटित किए जाने अपेक्षित थे। ऐसा करने की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 93.20 करोड़ का कम आवंटन हुआ।

इसके अलावा धारा 35(1)(i) के अन्तर्गत राजस्व खर्चों और अधिनियम की धारा 35(1)(iv) तथा 35 (2एबी) के अन्तर्गत पूंजीगत खर्चों के संबंध में ₹ 58.33 करोड़ की शेष भारित कटौती किंचित आवंटित नहीं की गई थी जो ऊपरउल्लिखित अनुपात में गोवा यूनिट को ₹ 40.37 करोड़ बनती थी। इस प्रकार उपर्युक्त के परिणामस्वरूप ₹ 133.57 करोड़ (₹ 93.20 + ₹ 40.37) का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 45.33 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

ख. प्रभार : सीआईटी मध्य, हैदराबाद
निर्धारिती : हेटरो ड्रग्स लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2009-10
पैन : AAACH5071K

निर्धारिती ने ₹ 98.19 करोड़ निगम उपरिव्यय का दावा किया जिसे टर्नओवर के आधार पर सभी यूनिटों को आवंटित नहीं किया गया था। निर्धारिती ने ₹ 14.10 करोड़ के स्थान पर ₹ 81.36 लाख आवंटित किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 13.29 करोड़ का धारा 80 आईसी के अन्तर्गत कटौती का अधिक दावा हुआ जिसमें ₹ 4.52 करोड़ के परिणामी कम कर उदग्रहण के साथ उतनी आय का अवनिर्धारण अन्तर्ग्रस्त है। आईटीडी यह कहते हुए आपत्ति स्वीकार नहीं की कि ऐसे आवंटन के लिए अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि खर्चों की प्रकृति पात्र तथा अपात्र यूनिटों दोनों के लिए सामान्य थी। इसके अलावा यह एक सामान्य सिद्धान्त है कि सभी निगम उपरिव्यय, जो पात्र तथा अपात्र यूनिटों को सामान्य हैं, संविभाजित किए जाने हैं और अधिनियम में कोई प्रावधान करना अपेक्षित नहीं है। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

ग. प्रभार : सीआईटी एलटीयू, मुम्बई
निर्धारिती : ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2007-08 से 2010-11
पैन : AAACG2207L

निर्धारिती ने आरएण्डडी खर्चों की भारित कटौती के आवंटन के लिए गलत¹⁸ बिक्री टर्नओवर अनुपात का उपयोग किया जो सही से कम था और एओ ने उसे स्वीकार

¹⁸ व्यक्तिगत यूनिट की विनिर्मित बिक्री और सभी यूनिटों की विनिर्मित बिक्री के पण्यवर्त के बीच अनुपात लेने के स्थान पर इसने व्यक्तिगत यूनिट की विनिर्मित बिक्री और सभी यूनिटों की सकल बिक्री (बेचे माल के टर्नओवर सहित) के बीच अनुपात का उपयोग किया। चूंकि आरएण्डडी का लाभ केवल विनिर्मित माल द्वारा लिया गया था और बेचे माल द्वारा नहीं इसलिए इसे अनुपात निकालने से बाहर किया जाना अपेक्षित था। सही अनुपात गलत अनुपात की अपेक्षा अधिक होगा।

किया। उन वर्षों के दौरान अनुपात में अन्तर 0.93 प्रतिशत से 3.15 प्रतिशत के बीच था। इसके कारण ₹ 319.15 करोड़ की कुल भारित कटौती में से उपर्युक्त वर्षों के लिए ₹ 167.36 करोड़ के स्थान पर पात्र यूनिटों (80 आईबी यूनिट गोवा में और 80 आईसी यूनिट बददी में) को ₹ 156.96 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। निम्नतर टर्नओवर अनुपात के कारण आरण्डडी खर्च के लिए भारित कटौती के निम्नतर आवंटन के परिणामस्वरूप उपर्युक्त नि.व. के लिए ₹ 10.40 करोड़ का कुल अवनिर्धारण ₹ 3.50 करोड़ के परिणामी कम कर उदग्रहण के साथ हुआ। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

इसने दर्शाया कि आईटीडी ने यह सुनिश्चित करने कि आरण्डडी से सामान्य खर्च अथवा भारित कटौती, कौन सी मुक्त/अमुक्त यूनिटें और बहू अवस्थापनक यूनिटें उससे लाभान्वित, सभी लाभार्थी यूनिटों को उचित रूप से आवंटित किए गए थे और अदेय छूटों/कटौतियों/रियायतों के दावे नहीं किए गए थे, के लिए सुस्पष्ट प्रणाली स्थापित नहीं की हैं।

एओज ने अधिनियम के प्रावधानों में निर्दिष्ट शर्तों का सत्यापन किए बिना निर्धारितियों को रियायतें/कटौतियां/छूट/राहत अनुमत किए।

3.2.2 रियायतों/कटौती/छूट/राहत की अनुमति

अध्याय VIक और धारा 10 उनमें निर्दिष्ट कुछ शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन किसी निर्धारिती की कुल आय संगणना में कुछ कटौतियों का प्रावधान करते हैं। धारा 80 आईबी/धारा 80आईसी इन धाराओं के अन्तर्गत उपक्रम से लाभों तथा अभिलाभों के संबंध में पहले पांच नि.व. और अगले पांच नि.व. के लिए क्रमशः 100 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत कटौतियों का प्रावधान करती हैं।

हमने 13 राज्यों¹⁹ में 26 मामले देखे जिनमें एओ ने उनकी उचित जांच किए बिना रियायतें/कटौती/छूट/राहत अनुमत की थीं जिनमें ₹ 158.89 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है (दिखे बाक्स 3.6)।

¹⁹ आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल

बाक्स 3.6: अधिक अथवा उपनियमित रियायत/छूट/कटौती/बटटा/राहत

क. प्रभार	: सीआईटी-॥ इन्दौर
निर्धारिती	: प्लेथिको फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2006-07 से 2009-10
पैन	: AABCP3063G

हमने देखा कि धारा 143(3)/153ए के अन्तर्गत सम्पन्न निर्धारण में लेखापरीक्षक जिसका नाम कांधला स्थित निर्धारिती की पात्र सेज यूनिट के लेखा प्रमाणन पर दर्ज था, ने शपथ पर बताया कि उसने उसकी लेखापरीक्षा नहीं की थी। इसलिए नि.व. 2006-07 से 2009-10 तक के लिए क्रमशः ₹ 68.03 करोड़, ₹ 80.88 करोड़, ₹ 121.46 करोड़ तथा ₹ 127.50 करोड़ तक निर्धारिती को अनुमत छूट सही नहीं थी क्योंकि निर्धारिती द्वारा भेजी गई फार्म 56एफ में रिपोर्ट उस लेखाकार द्वारा नहीं दी गई थी। इसलिए अधिनियम की धारा 10ए(5) के अनुसार छूट वापस ली जानी अपेक्षित थी जो नहीं ली गई थी। ऐसा करने की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 134.74 करोड़ के कर के कम उदग्रहण के साथ ₹ 397.87 करोड़ का कुल अवनिर्धारण हुआ। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

ख. प्रभार	: सीआईटी-॥ चण्डीगढ़
निर्धारिती	: वीनस रेमेडीज लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2011-12
पैन	: AAACV6524H

निर्धारिती ने अक्टूबर 2005 में प्रचालन आरम्भ किया और आरम्भिक नि.व. 2006-07 था। इसलिए वर्तमान नि.व. के लिए निर्धारिती 100 प्रतिशत लाभ पर दावित ₹ 16.24 करोड़ के स्थान पर लाभ के 30 प्रतिशत पर ₹ 4.87 करोड़ की कटौती का पात्र था। तथापि आईटीडी ने निर्धारिती द्वारा दावित कटौती को सीमित नहीं किया परिणामस्वरूप उतने अवनिर्धारण के साथ ₹ 11.37 करोड़ की कटौती की अधिक अनुमति हुई जिसमें ₹ 3.78 करोड़ का कर अन्तर्ग्रस्त था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

ग. प्रभार	: सीआईटी मध्य-॥, मुम्बई
निर्धारिती	: इण्डीको रेमेडीज लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2010-11
पैन	: AAACI0380C

एओ ने संवीक्षा निर्धारण के दौरान पात्र यूनिट (80 आईसी यूनिट) का लाभ गलती से ₹ 40.01 करोड़ के स्थान पर ₹ 41.70 करोड़ के रूप में अपनाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.69 करोड़ की अधिक कटौती हुई। इसके अलावा बिक्री टर्नओवर अनुपात में पात्र

तथा अपात्र यूनिटों के बीच आरएण्डडी खर्चों पर भारित कटौती²⁰ का आवंटन करते समय इसने पात्र यूनिट को ₹ 7.13 करोड़ के स्थान पर केवल ₹ 3.99 करोड़ आवंटित किया परिणामस्वरूप ₹ 3.13 करोड़ की अधिक कटौती हुई। इस प्रकार एओ ने ₹ 35.31 करोड़ की स्वीकार्य कटौती संगणित की और ₹ 34.62 करोड़ के उपलब्ध लाभ तक सीमित किया तथापि उपर्युक्त चर्चा के आधार पर स्वीकार्य कटौती केवल ₹ 30.69 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.93 करोड़ (₹ 34.62 करोड़ - ₹ 30.69 करोड़) की कटौती की अधिक अनुमति हुई जिसमें ₹ 1.18 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

इस प्रकार यह सुनिश्चित करने कि एओ द्वारा अनुमत किए जाने से पूर्व कटौतियों/ रियायतों/छूटों/बटटा/राहत की पूर्णतया संवीक्षा की जाती है, के लिए आईटीडी के पास सान्निहित प्रणाली नहीं थी।

एओ ने अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में मूल्यहास /कारोबार हानि /पूँजीगत हानि का समंजन/अग्रनयन अनुमत किया।

3.2.3 मूल्यहास/कारोबार हानि/पूँजीगत हानि का समंजन/अग्रनयन

धारा 72 आगामी नि.व. जहाँ समंजित न हुई मात्रा तक सुसंगत वर्ष के किसी शीर्ष के अन्तर्गत आय के प्रति हानि पूर्णतया समंजित नहीं हुई है, में समंजन के लिए हानि को आगे ले जाने का प्रावधान करती है।

हमने 11 राज्यों²¹ में 28 मामले देखे जिनमें एओ ने निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन में कारोबार व्यय अनुमत किया था जिसमें ₹ 27.77 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था (देखे बाक्स 3.7)।

बाक्स 3.7 कारोबार हानि के समंजन और मूल्यहास तथा कारोबार/पूँजीगत हानि का अग्रनयन अनुमत करने में अनियमितताएं

क. प्रभार	: सीआईटी-मध्य, हैदराबाद
निर्धारिती	: गायत्री बायो-आरगेनिक्स लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2011-12
पैन	: AAACG7384A

एओ ने अग्रनीत किए जाने के लिए नि.व. 1999-2000 से 2002-03 तक से सम्बन्धित ₹ 12.09 करोड़ की कारोबार हानि अनुमत की यद्यपि 8 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई

²⁰ आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भारित कटौती ₹ 18.27 करोड़ थी। तथापि एओ ने पात्र तथा अपात्र यूनिटों के बीच केवल 10.22 करोड़ का आवंटन किया।

²¹ आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल।

थी परिणामस्वरूप उस मात्रा तक अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 3.63 करोड़ का संभावित कर प्रभाव अन्तर्गस्त था। आईटीडी ने आपत्ति स्वीकार नहीं की थी परन्तु धारा 157 के अन्तर्गत आदेश पारित कर दिया (जुलाई 2014)।

ख. प्रभार : सीआईटी। दिल्ली
निर्धारिती : बॉश एण्ड लैम्ब आई केयर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2009-10
पैन : AABC7362G

एओ ने निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए ₹ 11.70 करोड़ (₹ 9.48 करोड़ + ₹ 2.22 करोड़) की अग्रेनीत कारोबार हानियों तथा अनवशोषित मूल्यहास के समंजन के बाद ₹ 19.96 करोड़ की आय निर्धारित कर अक्टूबर 2013 में निर्धारण पूर्ण किया। हमने पाया कि ₹ 11.70 करोड़ की हानियां समंजन करने के लिए उपलब्ध नहीं थीं क्योंकि निर्धारिती नि.व. 2007-08 तथा 2008-09 की आय पर निर्धारित था। इसलिए निर्धारण वर्ष 2009-10 में समंजन किए जाने के लिए कोई हानियां उपलब्ध नहीं थी। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 11.70 करोड़ की हानियों का गलत समंजन हुआ जिसमें ₹ 3.98 करोड़ के कर प्रभाव का कम उदग्रहण अन्तर्गस्त था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

ग. प्रभार : सीआईटी-पणजी
निर्धारिती : वैलेस फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2009-10
पैन : AACW1667Q

निर्धारिती का अपनी 80 आईसी यूनिट से ₹ 14.43 करोड़ का लाभ और अपनी गैर 80 आईसी यूनिट से ₹ 12.66 करोड़ की हानि थी। इस प्रकार निर्धारिती ने अपनी कुल आय ₹ 1.78 करोड़ और 80 आईसी यूनिट के लाभ की कटौती अनुमत करने, कुल आय तक से सीमित करने के बाद कुल कर योग्य आय शून्य संगणित की।

तथापि आईटीडी ने विवरणित आय में ₹ 6.20 करोड़ की वृद्धि की और कुल कर योग्य आय ₹ 6.20 करोड़ निर्धारित की और तदनुसार कर की गणना की। इससे असन्तुष्ट निर्धारिती ने यह कहते हुए कि उपलब्ध 80 आईसी कटौती निर्धारित आय से अधिक होने पर कर योग्य आय शून्य कर देयता के साथ शून्य होगी, धारा 154 के अन्तर्गत सुधार हेतु आवेदन किया।

एओ ने आदेश में सुधार किया परन्तु कुल कर योग्य आय शून्य निर्धारित करने के स्थान पर इसने ₹ 6.20 करोड़ की निर्धारित आय से गलती से ₹ 12.66 करोड़ घटाने के बाद 6.45 करोड़ की हानि निर्धारित की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.45 करोड़ का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 1.94 करोड़ का सम्भावित कर अन्तर्गस्त था।

आईटीडी ने आपत्ति स्वीकार कर ली है (अक्टूबर 2014) और 14 अक्टूबर 2014 को धारा 154 के अन्तर्गत गलती को सुधार लिया।

इसने दर्शाया कि एओज ने उपलब्ध इस प्रयोजन हेतु अपेक्षित ब्यौरों की उचित संवीक्षा किए बिना मूल्यहास/कारोबार हानि/पूँजीगत हानि का समंजन/अग्रनयन अनुमत किया जो अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था।

एओज ने अधिनियम के उल्लंघन में कारोबार से असम्बद्ध व्यय अनुमत किया

3.2.4 कारोबार व्यय की अनुमति

धारा 37 प्रावधान करती है कि कारोबार से असम्बद्ध कोई व्यय कारोबार खर्च के रूप में अनुमत नहीं किया जाना है। हमने 9 राज्यों²² में 22 मामले देखे जिनमें एओ ने निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन में कारोबार व्यय अनुमत किया था जिसमें ₹ 47.69 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था (देखें बाक्स 3.8)।

बाक्स 3.8 कारोबार व्यय की गलत अनुमति

क. प्रभार	: सीआईटी मध्य, पुणे
निर्धारिती	: टविलाईट लिटका फार्मा लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2012-13
पैन	: AAACL4246J

निर्धारिती द्वारा दाखिल आय की संगणना से पता चला कि उसकी कुल कारोबार आय ₹ 10.35 करोड़ थी और कुल करयोग्य आय ₹ 34.25 करोड़ की 80 आईसी कटौती अनुमत करने के बाद, कुल आय तक सीमित शून्य थी। एओ ने इस आधार पर निर्धारिती द्वारा दावित 80 आईसी कटौती को अस्वीकृत किया कि निर्धारिती ने तलाशी तथा जब्ती के दौरान स्वयं प्रस्तुत किया था कि वह लेनदेनों में लगा था जो मात्र बही प्रविष्टियां थीं प्रकृति में परिचालन और प्रमाणिक नहीं थी और तदनुसार एओ ने गलती से ₹ 10.35 करोड़ के स्थान पर ₹ 34.25 करोड़ पर कर योग्य आय निर्धारित की।

इसके आगे हमने देखा कि एओ ने उसकी प्रामाणिकता सत्यापित किए बिना लाभ तथा हानि लेखे में डेबिट किए ₹ 51.61 करोड़ का बट्टा खाता अनुमत किया था जिसमें (i) "बट्टे खाते डाली गई असाधारण मद माल सूची " के प्रति ₹ 15.03 करोड़, जिसके लिए या तो वार्षिक रिपोर्ट में अथवा निर्धारण अभिलेखों में और कोई विघटन/ब्यौरा उपलब्ध नहीं था और (ii) निर्धारिती द्वारा दावित "बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण" के प्रति ₹ 36.58 करोड़ जो उसी आधार पर अस्वीकृत किया जाना था कि लेनदेन प्रामाणिक नहीं थे।

²² गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल

लेखापरीक्षा के अनुसार यह ध्यान में रखकर कि 80 आईसी कटौतियां एओ द्वारा अस्वीकृत की गई थी, निर्धारित आय ₹ 34.25 करोड़ के स्थान पर ₹ 61.96 करोड़ (₹ 10.35 + ₹ 51.61) होनी चाहिए थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 27.71 करोड़ तक आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 8.99 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

ख. प्रभार : सीआईटी- पुडुचेरी
निर्धारिती : डीएक्सएन हर्बल, मेन्युफेक्चरिंग इण्डिया (प्रा.) लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2008-09
पैन : AABCD4141M

निर्धारिती ने पूर्व वर्ष 2007-08 (नि.व. 2008-09) के दौरान विरोध स्वरूप अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में ₹ 2.97 करोड़ का भुगतान किया था और आय की संगणना में धारा 43बी के अन्तर्गत कटौती के रूप में उसका दावा किया था। तथपि निर्धारिती ने इस संबंध में किसी व्यय का दावा नहीं किया था। धारा 43बी के अनुसार कटौती केवल तभी स्वीकार्य है जब उसे निर्धारिती द्वारा खर्च किया गया हो और वास्तव में भुगतान किया गया हो। चूंकि न तो देयता उठायी गई थी और नही लाभ तथा हानि लेखा में व्यय के रूप में उसका दावा किया गया है इसलिए उसे अस्वीकृत किया जाना अपेक्षित था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.97 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 1.01 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था।

आईटीडी ने बताया (नवम्बर 2014) कि यद्यपि निर्धारिती ने विरोधस्वरूप भुगतान किया फिर भी उसे उत्पाद शुल्क विभाग से मांग नोटिस दिया गया था। इसलिए यह एक वैद्य सांविधिक देयता है जो विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख से पूर्व भुगतान पर धारा 43बी के अन्तर्गत स्वीकार्य है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आईटीडी ने यह प्रमाणित करने कि देयता उठायी गई है, के लिए उत्पाद शुल्क विभाग के मांग नोटिस की प्रति प्रस्तुत नहीं की है।

इस प्रकार एओज ने कारोबार कटौतियां अनुमत की जो अधिनियम के प्रावधानों और नियमों तथा समय समय पर जारी सीबीडीटी निर्देशों के अनुसार अनुमत नहीं की जानी चाहिए थीं।

एओज ने डीएसआईआर मार्ग निर्देशों में उल्लिखित शर्तों से सन्तुष्ट हुए बिना आरएण्डडी व्यय अनुमत किया।

3.2.5 आर एण्ड डी खर्चों की अनुमति

अधिनियम की धारा 35(2एबी) के अन्तर्गत भारित कटौती के दावे के अनुमोदन के लिए डीएसआईआर मार्गनिर्देश आरएण्डडी पर पूंजीगत तथा राजस्व व्ययों की पात्रता के लिए विभिन्न शर्तें प्रस्तुत करते हैं। उनमें उल्लिखित शर्तों को पूरा न करने वाले कोई व्यय आरएण्डडी व्यय पर भारित कटौती की गणना करने से पूर्व निकाल दिए जाते हैं।

हमने 5 राज्यों²³ में 14 मामले देखे जिनमें एओ ने निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन में आरएण्डडी व्ययों पर कटौतियां अनुमत की गई थीं जिनमें ₹ 77.40 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था (देखें बाक्स 3.9)।

बाक्स 3.9: आरएण्डडी व्ययों की गलत अनुमति

क. प्रभार	: सीआईटी-एलटीयू मुम्बई
निर्धारिती	: ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2009-10 से 2010-11
पैन	: AAACG2207L

अधिनियम की धारा 35 (2एबी) के अन्तर्गत भारित कटौती के दावे के अनुमोदन हेतु डीएसआईआर मार्गनिर्देश अनुमोदित आरएण्डडी केन्द्र के कुल व्यय(भूमि तथा भवन को छोड़कर) से अन्य के साथ ठेका अनुसंधान से आय कम करने का विशेषकर प्रावधान करते हैं।

संवीक्षा निर्धारण के दौरान एओ ने अनुमोदित आन्तरिक अनुसंधान तथा विकास सुविधा पर खर्च पर अधिनियम की धारा 35(2एबी) के अन्तर्गत निर्धारिती द्वारा यथा दावित भारित कटौती अनुमत की। तथापि आरएण्डडी पर निवल व्यय की गणना करते समय सकल आरएण्डडी व्यय से क्रमशः ₹ 52.32 करोड़ तथा ₹ 46.11 करोड़ की ठेका अनुसंधान से आय कम करने के स्थान पर उसने ₹ 36 करोड़ तथा ₹ 31.07 करोड़ ठेका अनुसंधान के प्रति खर्च को कम किया।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.32 करोड़ तथा ₹ 15.04 करोड़ के आरएण्डडी व्यय और क्रमशः ₹ 24.47 करोड़ तथा ₹ 22.56 करोड़ की अनुरूप भारित कटौती (150 प्रतिशत की दर पर) का अधिक दावा हुआ जिसमें ₹ 15.99 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

²³ आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नई दिल्ली

ख.	प्रभार	: सीआईटी V दिल्ली
	निर्धारिती	: रैनबैकसी लेबोरेटरीज
	निर्धारण वर्ष	: 2007-08
	पैन	: AAACR0127N

निर्धारिती ने आय की संगणना में 150 प्रतिशत की दर पर आन्तरिक आरएण्डडी पर किए गए ₹ 412.20 करोड़ (₹ 374.31 करोड़ + ₹ 37.89 करोड़) के व्यय पर भारित कटौती का दावा किया जो धारा 35(2एबी) के अन्तर्गत ₹ 618.30 करोड़ बनी। इसके अलावा लेखापरीक्षा ने देखा कि धारा 35(2एबी) के अन्तर्गत कटौती का दावा करने के लिए राजस्व आरएण्डडी व्यय में अनुमोदित सुविधाओं (डीएसआईआर द्वारा जारी फार्म 3सीएल के अनुसार) के बाहर किए गए चिकित्सीय परीक्षण पर खर्च की गई ₹ 42.35 करोड़ की राशि शामिल है। चूंकि ₹ 42.35 करोड़ का चिकित्सीय परीक्षण पर किया गया व्यय धारा 35(2एबी) के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकार्य व्यय नहीं था। उस रूप में ₹ 21.17 करोड़ का भारित भाग अस्वीकृत किया जाना चाहिए था। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 21.17 करोड़ की भारित कटौती का अधिक दावा हुआ परिणामतः उतनी आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 6.35 करोड़ का कर अन्तर्गस्त था। उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

इस प्रकार आईटीडी आरएण्डडी खर्चों तथा उनके सही मूल्य की पात्रता की जांच के लिए कोई प्रभावी तन्त्र नहीं रखता है।

एओज ने खर्च अनुमत किए जिन पर या तो स्रोत पर कर नहीं काटा गया था अथवा यदि काटा गया तब निर्धारित देय तारीख से पूर्व जमा नहीं किया गया।

3.2.6 खर्च अनुमत करने में गलती जिनपर टीडीएस काटा/जमा नहीं किया गया था

धारा 40(ए) (Iए) के अनुसार कोई ब्याज, कमीशन अथवा दलाली (किराया, रायल्टी), व्यावसायिक अथवा तकनीकी सेवाओं की फीस अथवा ठेकेकार अथवा उपठेकेदार को देय राशि आदि जैसे उनमें ब्यौरे हैं, जिनपर कर स्रोत पर कटौती योग्य (टीडीएस) है और काटा नहीं गया है अथवा काटने के बाद निर्धारित देय तारीख को अथवा उसके पूर्व भुगतान नहीं किया गया है तो ऐसी राशियां आय की संगणना में खर्च के रूप में अनुमत नहीं की जाएगी।

हमने 5 राज्यों²⁴ में 7 मामले देखे जिनमें एओ ने खर्च अनुमत किए थे जिन पर या तो टीडीएस काटा नहीं गया था अथवा काटा गया परन्तु निर्धारित प्रावधानों

²⁴ असम, गुजरात, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल

का उल्लंघन कर जमा नहीं किया गया जिनमें ₹ 5.91 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था (देखें बाक्स 3.10)।

बाक्स 3.10 खर्चे अनुमत करने में गलती जिन पर टीडीएस काटा/जमा नहीं किया गया

प्रभार	: सीआईटी-1, गुवाहाटी
निर्धारिती	: केण्डिडा एण्टरप्राइजेज
निर्धारण वर्ष	: 2010-11 से 2011-12
पैन	: AADFC9889N

निर्धारिती ने पी/एल लेखे में सेवा प्रभारों के प्रति क्रमशः ₹ 1.01 करोड़ एवं ₹ 1.24 करोड़ डेबिट किए। तथापि टीडीएस काटने और निर्धारित समय सीमा के अन्दर सरकारी खाते में उस का भुगतान करने के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य निर्धारण अभिलेखों

में उपलब्ध नहीं था। इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 40(ए)(1ए) के प्रावधान के अनुसार सम्पूर्ण राशि स्वीकार्य कटौती नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.25 करोड़ की कुल आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 95.66 लाख का कर अन्तर्गस्त था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

इसने दर्शाया कि मामलों जहाँ टीडीएस या तो काटा नहीं गया है अथवा काटा गया परन्तु जमा नहीं किया गया, में खर्चों की अस्वीकृति का प्रावधान एओज द्वारा उचित प्रकार लागू नहीं किया जा रहा है।

एओज ने बाद के वर्षों में विशेष खर्चों को अनुमत करने अथवा अस्वीकृत करने में संगतता बनाए नहीं रखी।

3.2.7 निर्धारण में असंगति

एओज से कुछ पहलू के संबंध में स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के संबंध में संगत आधार लिए जाने की अपेक्षा की जाती है। किसी विशेष नि.व. में की गई अस्वीकृति अनुवर्ती नि.व. में कायम रखा जाना चाहिए जब तक अन्यथा विभाग द्वारा निर्णय न किया जाए।

हमने महाराष्ट्र में एक निर्धारिती के 3 मामलों में देखा कि विशेष अस्वीकृति देने में एओ द्वारा संगति का पालन नहीं किया था जिसमें ₹ 149.93 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था(देखें बाक्स 3.11)।

बाक्स 3.11 निर्धारण में असंगति

प्रभार	: सीआईटी मध्य-IV, मुम्बई
निर्धारिती	: रजत फार्माकेम लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2006-07, 2008-09 तथा 2009-10
पैन	: AAACR6464N

अधिनियम की धारा 68 कुल कर योग्य आय में राशि जोड़ने का प्रावधान करती है यदि वह राशि निर्धारिती की बहियों में क्रेडिट हुई पाई जाती है और निर्धारिती या तो उस की प्रकृति अथवा स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एओ के विचार में सन्तोषजनक नहीं है।

एओ ने नि.व. 2003-04 से 2009-10 तक के लिए अधिनियम की धारा 153ए के साथ पठित धारा 144 के अन्तर्गत निर्धारिती का एक पक्षीय संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया (मई 2011)। इस मामले में निर्धारिती के परिसर में तलाशी एवं जब्ती कार्रवाई की गई थी जिसमें यह पाया गया था कि लेखा बहियां कानून द्वारा यथा प्रावधानित उचित तथा सही रीति में नहीं बनाई गई थीं। इनमें हेरफेर किया गया था और लेनदेनों के समर्थन में साक्ष्य नहीं रखते थे और इसलिए उन्हें अस्वीकार किया गया था। निर्धारिती को

लेनदारों की ऋण योग्यता के साक्ष्य सहित पूर्ण ब्यौरों के साथ देनदारों तथा लेनदारों की वर्ष वार सूची भेजने के लिए कहा गया था जिसे प्रस्तुत करने में निर्धारिती विफल हो गया था। इसलिए एओ ने दर्शाए विविध नए लेनदारों की राशि को आय में जोड़ दिया। तथापि ऐसे संवर्धन केवल 2005-06 तक सम्बन्धित नि.व. में किए गए थे और ₹ 99.02 करोड़, ₹ 98.56 करोड़ और ₹ 186.34 करोड़ की राशि के नए विविध लेनदारों के समान संवर्धन क्रमशः नि.व. 2006-07, 2008-09 तथा 2009-10 के लिए नहीं किए गए थे। ऐसा करने की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 383.92 करोड़ का अवप्रभार हुआ।

आगे यह देखा गया था कि नि.व. 2008-09 (वि.व. 2007-08) से सम्बन्धित तुलन पत्र में वर्ष के अन्त में विविध लेनदार ₹ 198.12 करोड़ दर्शाया गया है तथापि अगले वि.व. अर्थात् 2008-09 के तुलन पत्र में तुलना के लिए पूर्व वि.व. (अर्थात् 2007-08) के ब्यौरे दर्शाने वाले कालम में उसे ₹ 198.12 करोड़ के स्थान पर ₹ 256.26 करोड़ दर्शाया गया है। इस स्फीत प्रतिबिम्बन के कारण ₹ 58.14 करोड़ की विभेदक राशि नि.व. 2009-10 से सम्बन्धित आय में जोड़ी जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार इस मामले में कुल अवनिर्धारण ₹ 442.06 करोड़ का था जिसमें ₹ 149.93 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

एओज ने अधिनियम में प्रावधानों तथा इस संबंध में सीबीडीटी के निर्देशों के बावजूद निर्धारणों में गणितीय त्रुटियां की।

3.2.8 आय तथा कर की संगणना में गणितीय त्रुटियां

धारा 143 (3) प्रावधान करती है कि एओज को आय सही प्रकार अवधारित तथा निर्धारित करनी है। लेखाओं, अभिलेखों तथा विवरणी के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों के साथ विभिन्न दावों की संवीक्षा निर्धारणों में विस्तार में जांच की जानी अपेक्षित है। इस संबंध में सीबीडीटी ने समय समय पर निर्देश भी जारी किए हैं।

हमने 9 राज्यों²⁵ में 15 मामले देखे जिनमें एओ ने गणितीय त्रुटियां की जिनमें ₹ 14.65 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था (बाक्स 3.12 देखें)।

बाक्स 3.12: आय तथा कर की संगणना में गणितीय त्रुटियां

क.	प्रभार	: सीआईटी मध्य बंगलौर
	निर्धारिती	: दी हिमालय ड्रग कम्पनी
	निर्धारण वर्ष	: 2005-06
	पैन	: AADFT3025B

हमने देखा कि पूर्व में जारी ₹ 2.85 करोड़ का प्रतिदाय निर्धारिती द्वारा कुल देय मांग की गणना करते समय वापस नहीं जोड़ा था परिणामस्वरूप ₹ 4.00 करोड़ की मांग की कम गणना हुई। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और धारा 154 के अन्तर्गत नवम्बर 2013 में सुधार आदेश पारित किया गया था।

ख.	प्रभार	: सीआईटी-III, कोलकाता
	निर्धारिती	: एलाइड रेजिन्स एण्ड केमीकल्स लिमिटेड
	निर्धारण वर्ष	: 2008-09
	पैन	: AACCA8557D

हमने देखा कि निर्धारण आदेश में एओ ने ₹ 4.95 करोड़ की अनेक अस्वीकृतियां कीं। एओ ने उस राशि को जोड़ने के स्थान पर कुल आय से घटा दिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.97 करोड़ के परिणामी सम्भावित कर प्रभाव के साथ ₹ 9.90 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ। आईटीडी ने लेखापरीक्षा द्वारा यथा उल्लिखित गलती का धारा 154 के अन्तर्गत सुधार किया (अगस्त 2014)।

²⁵ आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल

ग.	प्रभार	: सीआईटी-1, हैदराबाद
	निर्धारिती	: डा. रेड्डी'ज रिसर्च फाउण्डेशन लिमिटेड
	निर्धारण वर्ष	: 2008-09
	पैन	: AABCR1733M

हमने देखा कि 10 मार्च 2014 को अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 143 (3) के अन्तर्गत निर्धारिती कम्पनी के निर्धारण के दौरान 25 अप्रैल 2011 को अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत ₹ 1.69 करोड़ का जारी प्रतिदाय पर निर्धारिती द्वारा देय कुल मांग की गणना करते समय विचार नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 2.11 करोड़ की मांग कम हुई। आईटीडी ने बताया (जुलाई 2014) कि लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार्य है।

इसने दर्शाया कि अनेक मामलों में निर्धारण की गुणवत्ता समय समय पर सीबीडीटी के निर्देशों के बावजूद गणितीय त्रुटियों से पीड़ित हुआ।

अधिनियम में विशेष प्रावधानों के बावजूद एओ ने विशेष प्रावधानों के अधीन आय का निर्धारण नहीं किया।

3.2.9 विशेष प्रावधान के अन्तर्गत आय का निर्धारण

धारा 115जेबी अंकित लाभ के निर्धारित प्रतिशत पर मैट के उदग्रहण का प्रावधान करती है यदि सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत कुल आय पर देय कर यथा निर्धारित कुछ वृद्धियों तथा विलोपनों के बाद अंकित लाभ की ऐसी प्रतिशतता की अपेक्षा कम है।

हमने 5 राज्यों²⁶ में 6 मामले देखे जिनमें एओ ने धारा 115 जेबी के अन्तर्गत आय का उचित प्रकार निर्धारण नहीं किया था जिसमें ₹ 6.11 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था (बाक्स 3.13 देखें)।

बाक्स 3.13 विशेष प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित न की गई आय		
क.	प्रभार	: सीआईटी । दिल्ली
	निर्धारिती	: आयुर्वेद लिमिटेड
	निर्धारण वर्ष	: 2009-10
	पैन	: AAECA4056B

एओ ने सामान्य प्रावधान के अन्तर्गत शून्य आय निर्धारित की। इसलिए निर्धारिती को अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 5.86 करोड़ के अंकित लाभ पर कर

²⁶ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल

भुगतान करना पड़ा। आगे लेखापरीक्षा ने देखा कि लाभ तथा हानि लेखे को डेबिट अशोध्य ऋणों के प्रावधान के संबंध में ₹ 35.00 लाख की राशि भी अंकित लाभ में जोड़ी जानी अपेक्षित थी। न तो निर्धारिती ने और न ही एओ ने धारा 115 जेबी के अन्तर्गत कर निर्धारित किया। ऐसा करने की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 6.21 करोड़ का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 70.40 लाख का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था। उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

ख. प्रभार : सीआईटी-एलटीयू, मुम्बई
निर्धारिती : इपका लेबोरेटरीज लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2009-10
पैन : AAACI1220M

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) में किसी उद्यमी द्वारा किए गए किसी कारोबार से उपार्जित अथवा उदभूत आय निम्नतम वैकल्पिक कर (मैट) की संगणना के प्रयोजन हेतु अंकित लाभ संगणित करते समय गणना में नहीं लिया जाना है। इसके अलावा जैसा विभिन्न न्यायालय निर्णयों²⁷ द्वारा स्पष्ट किया गया, सेज से ऐसी आय अधिनियम की धारा 10एए के अन्तर्गत मुक्त है और इसलिए सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत कुल आय की संगणना के भाग के रूप में नहीं मानी जाएगी।

निर्धारिती ने मैट के प्रयोजन हेतु अंकित लाभ की संगणना में पीतमपुर स्थित अपनी सेज यूनिट में ₹ 15.29 करोड़ की हानि को माना और एओ ने उसे अनुमत किया जो स्वीकार्य नहीं था। इसके परिणामस्वरूप उस मात्रा तक अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 1.73 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था। इसके अलावा निर्धारिती ने भी सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत कुल आय की संगणना में ऊपर उल्लिखित हानि को माना था और एओ ने उसे स्वीकार किया था चूंकि इस मामले में निर्धारिती द्वारा देय कर निम्नतम वैकल्पिक कर था इसलिए निर्धारिती को उपलब्ध मैट क्रेडिट ₹ 1.73 करोड़ की उसी राशि तक अधिक था।

बाद में जब निर्धारिती लेखापरीक्षा में यथा उल्लिखित मैट के अन्तर्गत ₹ 1.73 करोड़ का और भुगतान करता है तो निर्धारिती को नया मैट उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि उसके पास पहले ही उस मात्रा तक अधिक क्रेडिट था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्तूबर 2014)।

इसने दर्शाया कि अनेक मामलों में धारा 115 जेबी के अन्तर्गत आय उनमें अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार निर्धारित नहीं की जा रही थी।

²⁷ साइंटिफिक एटलांटा बनाम एसीआईटी 129 टीटीजे 273 (चेन्नई) (एसबी), सीआईटी बनाम योकोगावा (इण्डिया) लि मि. 341 आईटीआर 385 (कर्ना), सीआईटी बनाम ब्लैक एण्ड वीच कंसाल्टिंग 348 आईटीआर 72 (बम्बई), सीआईटी बनाम टीईआई टेकनालाजीज 78 डीटीआर 225 (दिल्ली) तथा अन्य निर्णय

एओज ने अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारितियों की आय का निर्धारण नहीं किया यद्यपि वह विशेष रूप से मुक्त नहीं थी।

3.2.10 सामान्य प्रावधान के अन्तर्गत आय का निर्धारण

धारा 5 प्रावधान करती है कि किसी पूर्व वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय में किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न सभी आय शामिल होती है जो प्राप्त है अथवा प्राप्त की जानी मानी गई है अथवा जो ऐसी पूर्व वर्ष के दौरान उपार्जित होती है अथवा उत्पन्न होती है जब तक अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कर से मुक्त नहीं होती है।

हमने 8 राज्यों²⁸ में 16 मामले देखे जिसे एओ ने अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत आय का निर्धारण नहीं किया था जिसमें ₹ 84.21 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था (बाक्स 3.14 देखें)।

बाक्स 3.14: सामान्य प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित न की गई आय

क.	प्रभार	: सीआईटी ॥ बडोदरा
	निर्धारिती	: सन फार्मास्युटिकल्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (एसपीआईएल)
	निर्धारण वर्ष	: 2008-09 to 2010-11
	पैन	: AADCS3124K

निर्धारिती कम्पनी (एसपीआईएल) ने भागीदारी फर्म में. सन फार्मास्युटिकल इण्डस्ट्रीज (एसपीआई) से यह कहते हुए ₹ 141.72 करोड़ प्राप्त किए कि यह फर्म से पारिश्रमिक था और यह कहते हुए इस आय पर धारा 28(v) के अन्तर्गत छूट का दावा किया कि फर्म ने पहले ही अपनी आय में इस राशि को जोड़ दिया है। हमने भागीदारी पत्र के

ब्यौरों से पाया कि इस प्रकार प्राप्त आय तकनीकी, विपणन तथा वितरण सहायता और एसपीआई (फर्म) की बाबत निष्पादित कुछ अन्य कार्यों के लिए सेवा प्रभारों की प्रकृति की थी।

इसलिए एसपीआईएल की उपर्युक्त आय पारिश्रमिक की प्रकृति की न होने पर परन्तु सेवा प्रभार होने पर कर भारित की जानी अपेक्षित थी। ऐसा करने की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 141.72 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 48.17 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्तूबर 2014)।

²⁸ असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान पश्चिम बंगाल

ख. प्रभार	: सीआईटी मध्य-III, कोलकाता
निर्धारिती	: निक्सिल फार्मास्युटिकल्स स्पेशियल्टीज लिमिटेड
निर्धारित वर्ष	: 2010-11
पैन	: AABCN6977H

निर्धारिती के तुलन पत्र में निवेश के ब्यौरों से पता चला कि 31 मार्च 2010 को एक अन्य कम्पनी में. बासिल इण्टरनेशनल लिमिटेड ने निर्धारिती कम्पनी में ₹ 24.33 करोड़ का निवेश किया था। जबकि में. बासिल इण्टरनेशनल लिमिटेड के निवेश ब्यौरें निर्धारिती के इक्विटी शेयरोंमें मात्र ₹ 9.44 करोड़ दर्शाते हैं। चूंकि निर्धारिती के लेखाओं में वर्ष के दौरान शेयरों की कोई बिक्री नहीं दर्शाई गई इसलिए इस प्रकार प्रदर्शित अधिक राशि धारा 69 के अन्तर्गत अघोषित स्रोत से आया मानी जानी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.89 करोड़ का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 4.24 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्तूबर 2014)।

ग. प्रभार	: सीआईटी-एलटीयू, बंगलौर
निर्धारिती	: बायोकोन लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2010-11
पैन	: AAACB7461R

हमने पाया कि एओ ने निर्धारण में कुल आय संगणित करते समय ₹ 8.83 करोड़ की अन्य स्रोत से आय पर विचार नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप उतनी आय की कम संगणना हुई जिसमें ₹ 3 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

आईटीडी ने बताया है (दिसम्बर 2014) कि अधिनियम की धारा 147 के अन्तर्गत मामला पुनः खोला गया है और संशोधित विवरणी दाखिल करने का उसे निर्देश देते हुए निर्धारित को धारा 148 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 1-10-2014 जारी किया गया है।

इसने दर्शाया कि अनेक मामलों में अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत आय समय समय पर जारी सीबीडीटी के निर्देशों के बाबजूद निर्धारित नहीं की जा रही थी।

निर्धारण अधिकारियों ने पूंजीगत अभिलाभों का गलत वर्गीकरण किया तथा संगणना की।

3.2.11 पूंजीगत लाभों का वर्गीकरण और संगणना

अधिनियम की धारा 45 प्रावधान करती है कि किसी पूंजीगत परिसम्पत्ति के हस्तान्तरण से उत्पन्न कोई लाभ तथा अभिलाभ पूंजीगत अभिलाभ शीर्ष के अन्तर्गत आयकर को प्रभार्य होंगे।

अधिनियम की धारा 50बी प्रावधान करती है कि मंदी बिक्री से उत्पन्न कोई लाभ तथा अभिलाभ दीर्घावधि पूंजीगत परिसम्पत्ति के हस्तान्तरण से उत्पन्न पूंजीगत अभिलाभ के रूप में आयकर को प्रभार्य होंगे।

हमने मुम्बई में एक मामला देखा जिसमें एओ ने पूंजीगत अभिलाभ के अन्तर्गत आय का उचित प्रकार निर्धारण नहीं किया था जिसमें ₹ 0.74 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था (बाक्स 3.15 देखें)

बाक्स 3.15 पूंजीगत अभिलाभों का गलत वर्गीकरण तथा संगणना

क. प्रभार	: सीआईटी-एलटीयू, मुम्बई
निर्धारिती	: ग्लेनमार्क फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2009-10
पैन	: AAACG2207L

निर्धारिती ने ₹ 750 करोड़ के लिए कारोबार हस्तान्तरण अनुबन्ध के अन्तर्गत 01 अप्रैल 2008 को अंकलेश्वर तथा गोवा स्थित अपनी दो जेनरिक यूनितों को बेचा था। तथापि इस बिक्री प्रतिफल से कारोबार की लागत डेबिट करते समय दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ निकालने के लिए इन यूनितों के पूंजीगत चालू कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) का अंकित मूल्य ₹ 54.91 करोड़ माना। जबकि 31 मार्च 2008 को सीडब्ल्यूआईपी का अन्तःशेष मात्र ₹ 51.66 करोड़ था जैसा तुलन पत्र के स्थाई परिसम्पत्ति अनुसूची की टिप्पणियों में प्रतिबिम्बित किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.25 करोड़ के दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभों का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 73.65 करोड़ लाख के कर का कम उदग्रहण अन्तर्ग्रस्त था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

3.2.12 अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन

अधिनियम की धारा 92ई के साथ पठित धारा 92डी प्रावधान करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन में भाग लेता है, को निर्धारित सूचना तथा दस्तावेजों का रखरखाव तथा अनुरक्षण करना और इस संबंध में किसी लेखाकार से निर्धारित तारीख से पूर्ण फार्म 3 सीईबी में रिपोर्ट प्राप्त तथा भेजनी पड़ती है। इसके अलावा अधिनियम की धारा 271 एए के अनुसार ऐसी सूचना के रखरखाव तथा अनुरक्षण करने और अथवा यथा अपेक्षित ऐसे लेन देन की रिपोर्ट करने में विफलता अथवा गलत सूचना या दस्तावेज का अनुरक्षण करने अथवा भेजने पर किए गए अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन के मूल्य के दो प्रतिशत की दर पर शास्ति लगेगी।

हमने महाराष्ट्र में अन्तरण मूल्य निर्धारण कार्यों में अथवा आईटीडी द्वारा इसका प्रभाव देने में त्रुटियों वाले पांच मामलों देखें जिनमें ₹ 7.58 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था (बाक्स 3.16 देखें)।

बाक्स 3.16 अन्तरण मूल्य निर्धारण में अनियमितताएं

क. प्रभार	: सीआईटी-एलटीयू, मुम्बई
निर्धारिती	: ग्लेनमार्क जेनरिक लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2009-10
पैन	: ACCG9820D

अधिनियम की धारा 92ई के साथ पठित धारा 92 डी प्रावधान करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन में भाग लेता है, को निर्धारित सूचना तथा दस्तावेजों का रखरखाव तथा अनुरक्षण करना और इस संबंध में किसी लेखाकार से निर्धारित तारीख से पूर्व फार्म 3 सीईबी में रिपोर्ट प्राप्त करना तथा भेजनी पड़ती है। इसके अलावा अधिनियम की धारा 271 ए के अनुसार ऐसी सूचना के रखरखाव तथा अनुरक्षण करने और अथवा यथा अपेक्षित ऐसे लेन देन कि रिपोर्ट करने में विफलता अथवा गलत सूचना या दस्तावेज का अनुरक्षण करने अथवा भेजने पर किए गए अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन के मूल्य के दो प्रतिशत की दर पर शास्ति लगेगी।

हमने देखा कि निर्धारिती ने मै. ग्लेनमार्क जेनरिकस इं, यूएसए द्वारा ग्राहक को एक समय अतिरिक्त बिक्री अनुमतियों के प्रति कम्पनी के शेयर के लिए भुगतान के कारण लाभ एवं हानि लेखे में ₹ 111.11 करोड़ के कुल अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन दर्शाए थे। उसे फार्म 3 सीडी में कर लेखापरीक्षा रिपोर्टर द्वारा भी प्रमाणित किया गया था। तथापि निर्धारिती द्वारा उसे फार्म सं. 3 सीईबी में न तो सूचित किया गया था और न ही अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी अथवा एओ द्वारा संज्ञान में लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 111.11 करोड़ तक फर्म सं. 3 सीईबी में अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन की सूचना नहीं हुई जिस पर 2 प्रतिशत की दर पर ₹ 2.22 करोड़ की शास्ति लगनी था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

ख. प्रभार	: सीआईटी-VIII, मुम्बई
निर्धारिती	: फाइजर लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2010-11
पैन	: AAACE3334M

एओ ने निर्धारिती द्वारा अपने सहायक उद्यमों को प्रदत्त लाभ तथा हानि लेखे को डेबिट ₹ 18.38 करोड़ के खर्चे अनुमत किए। तथापि फार्म 3 सीईबी में लेखाकार ने केवल ₹ 10.46 करोड़ का सहायक उद्यमों के साथ लेन देन प्रमाणित किया। इसके

परिणामस्वरूप फार्म 3 सीईबी में लेखाकार द्वारा जो प्रमाणित किया था, के अतिरिक्त ₹ 7.92 करोड़ के व्यय का अधिक दावा हुआ जिसके कारण उतनी आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 2.69 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्तूबर 2014)।

3.2.13 अन्य मामलें

हमने विविध प्रकृति जैसे अनंतिम खर्चों की अनुमति, ब्याज के उदग्रहण में गलती, जाली खरीद खर्चों की अनुमति आदि के 5 राज्यों²⁹ में 13 मामले भी देखे जिनमें ₹ 12.15 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गस्त था (बाक्स 3.17-3.20 देखें)।

बाक्स 3.17 विविध गलतियों के निदेशी मामले

खर्चों के प्रावधान अनुमत करने में गलती

धारा 37 के अनुसार कारोबार अथवा वृत्ति के प्रयोजनों हेतु पूर्णतया अथवा एक मात्र रूप से लगाया गया अथवा खर्च किया गया कोई व्यय (धारा 30 से 36 तक में वर्णित प्रकृति का खर्च न होने पर और पूंजीगत व्यय अथवा निर्धारिती का व्यक्तिगत खर्च की प्रकृति का न होने पर) कारोबार अथवा वृत्ति को लाभ तथा अभिलाभ " शीर्ष के अन्तर्गत प्रभार्य आय की संगणना में अनुमत किया जाएगा। इसलिए किया गया कोई प्रावधान स्वीकार्य खर्च नहीं है।

क. प्रभार	: सीआईटी एलटीयू मुम्बई
निर्धारिती	: ग्लेनमार्क फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11
पैन	: AAACG2207L

हमने देखा कि निर्धारिती ने " उपदान तथा छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान" के लिए नि.व. 2008-09 के लिए ₹ 2.03 करोड़, नि.व. 2009-10 के लिए ₹ 4.58 करोड़, नि.व. 2010-11 के लिए ₹ 3.46 करोड़ की राशि का प्रावधान किया। आईटी अधिनियम की धारा 37 के अनुसार किया गया कोई प्रावधान स्वीकार्य व्यय नहीं है। इसलिए इसे अस्वीकृत किया जाना चाहिए था और अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत आय की संगणना करते समय कुल आय को जोड़ा जाना चाहिए था। परन्तु न तो निर्धारिती ने और न ही विभाग ने इस आय को जोड़ा है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.43 करोड़ के परिणामी व्यय उदग्रहण के साथ ₹ 10.08 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्तूबर 2014)।

²⁹ केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल

ख. प्रभार	: सीआईटी त्रिवेन्द्रम
निर्धारिती	: केरल मेडिकल सर्विस कार्पोरेशन
निर्धारण वर्ष	: 2010-11
पैन	: AADCK4029M

हमने देखा कि पी एण्ड एल लेखा को डेबिट ₹ 1.42 करोड़ की राशि का आयकर हेतु प्रावधान कुल आय संगणित करते समय वापस नहीं जोड़ा गया था। गलती के परिणामस्वरूप उतनी मात्रा का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 48.11 लाख के कर का कम उदग्रहण अन्तर्ग्रस्त था। आईटीडी ने आपत्ति स्वीकार कर ली।

बाक्स 3.18 विविध गलतियों के निदर्शी मामलें

जाली खरीद खर्चों की अनुमति

धारा 37 के अनुसार किसी प्रयोजन, जो एक अपराध है अथवा जो कानून द्वारा प्रतिबन्धित है, के लिए निर्धारिती द्वारा किया गया कोई व्यय कारोबार अथवा वृत्ति के प्रयोजन हेतु किया गया नहीं माना जाएगा और ऐसे खर्च के संबंध में कोई कटौती अथवा अनुमति नहीं दी जाएगी।

महाराष्ट्र राज्य के बिक्री कर विभाग ने अपनी जांच के दौरान भारी घोटाले का पर्दाफाश किया था जिसमें उन्होंने पाया था कि कुछ व्यापारी वास्तविक बिक्री/ खरीद लेन देन बिना बीजक जारी कर रहे थे जो कुछ नहीं था परन्तु हवाला लेन देन था। उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के बिक्री कर विभाग की वेबसाइट पर ऐसे हवाला व्यापारियों की सूची प्रकाशित करना आरम्भ किया। ऐसे जाली व्यापारियों से की गई खरीद निर्धारितियों के लिए स्वीकार्य कटौती नहीं हैं।

प्रभार	: सीआईटी-VIII, मुम्बई
निर्धारिती	: हिरेन आरगोकम लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2009-10
पैन	: AAACH0977J

एओ ने महाराष्ट्र सरकार के बिक्री कर विभाग की वेबसाइट पर जाली व्यापारियों की सूची में शामिल एक व्यापारी, मै. उत्काण्ठा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड जिससे निर्धारिती ने ₹ 13.20 करोड़ की खरीदें दर्शाई थीं, का नाम सत्यापित किए बिना संवीक्षा निर्धारण पूरा किया और इसलिए ये खर्च स्वीकार्य नहीं थे। ऐसा करने की चूक के परिणामस्वरूप उतनी मात्रा का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 3.96 करोड़ का सम्भावित कर प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

आईटीडी ने अपने उत्तर में यह कहते हुए आपत्ति स्वीकार नहीं की कि लेखापरीक्षा ने तीसरे पक्ष सूचना पर भरोसा किया था। आईटीडी का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि व्यापारी का नाम महाराष्ट्र सरकार के बिक्री कर विभाग की वेबसाइट पर जाली

व्यापारियों की सूची में प्रकाशित था और स्वयं आईटीडी प्रवृत्ति में जाली खरीदों की अस्वीकृतियों के लिए उस वेबसाइट से सूचना का उपयोग करता है। इसके अलावा यह न्याय निर्णोत³⁰ है कि विभिन्न राज्य/केन्द्र सरकार अधिकारियों द्वारा अनुरक्षित अभिलेख साक्ष्य के महत्वपूर्ण भाग हैं।

बाक्स 3.19: विविध गलतियों के निदर्शी मामले

कर जमा न करना

क. प्रभार	: सीआईटी-॥ चण्डीगढ़
निर्धारिती	: बीनस रेमेडीज लिमि.
निर्धारण वर्ष	: 2011-12
पैन	: AAACV6524H

निर्धारिती कम्पनी ने 30.09.2011 को नि.व.2011-12 के लिए ₹ 2.74 करोड़ का लाभांश घोषित किया। धारा 115(ओ) के प्रावधानों के अनुसार ₹ 44.16 लाख का अतिरिक्त कर 15 अक्टूबर 2011 से पूर्व जमा किया जाना अपेक्षित था। निर्धारिती ने कर जमा नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी ₹ 44.16 लाख की कर मांग की बकाया शेष राशि के साथ चूककर्ता हो गई। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

ब्याज के उदग्रहण में गलती

ख. प्रभार	: सीआईटी मध्य-IV, मुम्बई
निर्धारिती	: रजत फार्माकेम लिमि.
निर्धारण वर्ष	: 2008-09
पैन	: AAACR6464N

एओ ने मई 2011 में अधिनियम की धारा 153 ए के साथ पठित धारा 144 के अन्तर्गत एक पक्षीय संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। इस मामले में निर्धारिती ने न तो धारा 139(1) के अन्तर्गत विवरणी दाखिल की और न ही अधिनियम की धारा 153ए के अन्तर्गत दाखिल की। एओ ने निर्धारिती की कुल आय ₹ 283.98 करोड़ पर निर्धारित की जिस पर ₹ 96.52 करोड़ का कर उदग्रहण था। हमने देखा कि 32 महीने (01-10-2008 से 31-05-2011) के लिए 1 प्रतिशत की दर पर उदग्रहण धारा 234 ए के अन्तर्गत ब्याज ₹ 30.89 करोड़ बनी तथापि एओ ने केवल ₹ 29.92 करोड़ उदग्रहीत की थी। इसलिए ₹ 96.52 लाख का धारा 234 ए के अन्तर्गत ब्याज का कम उदग्रहण हुआ था। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

³⁰ मोतीपुर सुगर फैक्टरी (प्रा.) लिमि. बनाम सीआईटी (1974)95 आईटीआर 401-पटना (उन्या), सीताराम माइनिंग कम्पनी बनाम सीआईटी (1968) 68 आईटीआर 1 (आ प्र) उ न्या

बाक्स 3.20 विविध गलतियों के निदर्शी मामले	
प्रतिदायों पर अधिक अथवा ब्याज का उदग्रहण	
च. प्रभार	: सीआईटी-IV, कोलकाता
निर्धारिती	: ओरगानोन (इण्डिया) लिमिटेड
निर्धारण वर्ष	: 2007-08
पैन	: AAACI6949R
<p>एओ ने धारा 234डी के अन्तर्गत ₹ 16.78 लाख के स्थान पर ₹ 1.37 करोड़ का ब्याज उदग्रहीत किया। गलती के परिणामस्वरूप धारा 234डी के अन्तर्गत ₹ 1.20 करोड़ के ब्याज का अधिक उदग्रहण हुआ। आईआईटी ने सितम्बर 2012 में धारा 154 के अन्तर्गत गलती का सुधार किया। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।</p>	

3.3 निष्कर्ष

कर राजस्व में सहयोग तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के ऊपर आवश्यक नियंत्रण करने के लिए उचित मशीनरी/प्रणाली की विद्यमानता कर मूल्यांकन करने के लिए हमने औषधि क्षेत्र में निर्धारितियों पर एक अध्ययन किया। क्षेत्रवार डाटा अनुरक्षित न करने और आयकर विवरणी तथ उत्पाद शुल्क विवरणी में घोषित टर्नोवर के प्रति सत्यापन हेतु तन्त्र विद्यमान न होने जैसी प्रणाली कमजोरियों के अतिरिक्त हमने भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई), राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) जैसे नियामक निकायों के निर्देशों/मार्गनिर्देशों के अननुपालन का उल्लेख किया।

अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में हमने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्टता लाने का भी सुझाव दिया ताकि निर्धारण अधिकारियों द्वारा भिन्न विचार नहीं लिए जा सकें, निर्धारणों में संगति हो और मुकदमों का परिहार किया जा सके।

3.4 सिफारिशें

क. चिकित्सक के नमूनों सहित फ्रीबीज के रूप में माने जाने वाले खर्चों की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए सीबीडीटी निर्देश जारी करे। इसके अलावा बिक्री प्रोत्साहन खर्चों से फ्रीबीज की प्रकृति में खर्चों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए ऐसे खर्चों की कटौती का दावा करने वाले निर्धारितियों के लिए सीबीडीटी एक उपयुक्त तन्त्र विकसित करे।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2015) कि फ्रीबीज किस से बनता है, 10 दिसम्बर 2009 को यथा संशोधित भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार तथा आधार शास्त्र) विनियम 2002 के मार्गनिर्देशों में निर्धारित है और इसलिए कथित मार्गनिर्देशों में कोई परिवर्तन/वृद्धि/विलोचन केवल उस निकाय द्वारा किया जा सकता है। मंत्रालय ने आगे बताया (जनवरी 2015) कि प्रत्येक मामले में विषय उसके गुणदोष के आधार पर एओ द्वारा निर्धारित किया जाता है और उपचारी कार्रवाई एओ के पास उपलब्ध है। मंत्रालय ने आगे बताया कि आईटीआर में फ्रीबीज की प्रकृति में खर्चों के ब्यौरे बनाना इसको भारी भरकम बना देगा।

लेखापरीक्षा का मत है कि इस संबंध में सीबीडीटी निर्देशों में स्पष्टता की कमी के कारण एओ भिन्न विचार ले रहे हैं इसलिए मंत्रालय उचित कार्रवाई कर सकता है ताकि एओ भविष्य में सुसंगत कार्रवाई कर सके।

- ख. सीबीडीटी इस संबंध में विवादित तथा शेष विविध व्याख्याओं को प्रस्तुत करने के लिए फ्रीबीज के प्रति खर्चों के अस्वीकरण की प्रभावी तारीख स्पष्टता से निर्दिष्ट करें।

मंत्रालय ने बताया कि सीबीडीटी का परिपत्र दिनांक 01 अगस्त 2012 प्रवृत्ति में मात्र स्पष्टकारी था और एओ एमसीआई के विद्यमान/संशोधित मार्गनिर्देशों के आधार पर फ्रीबीज की कोई अस्वीकृति करते हैं और इस मामले में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं हैं।

लेखापरीक्षा का मत है कि परिपत्र में प्रभावी तारीख का अभाव एओज को भिन्न विचारों का और अन्ततः मुकदमों का कारण बन सकता है। इसलिए तारीख जिससे सीबीडीटी के निर्देश लागू होंगे, का प्रत्येक निर्देश/परिपत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए अर्थात् भावी अथवा पूर्वव्यापी।

- ग. मंत्रालय ऐसे आवंटन के आधार और कार्यचालन के साथ साथ सभी सामान्य खर्चों अथवा भारित कटौतियों का आवंटन दर्शाते हुए या तो विवरणी के साथ अथवा निर्धारण अभिलेखों के साथ दाखिल किए जाने के लिए एक मानक फार्म लागू करें।


मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2015) कि यह एक अनुपालन मामला है और प्रत्येक मामले के आधार पर कार्रवाई की जानी है। संवीक्षा निर्धारणों के दौरान एओ ऐसे सभी ब्यौरे मांगने के लिए शक्ति सम्पन्न हैं।

तथापि लेखापरीक्षा का अभी भी यह मत है कि निर्धारण अभिलेखों में सामान्य खर्चों के आवंटन का आधार दर्शाने की आवश्यकता है।

- घ. मंत्रालय सामान्यता डीएसआईआर की शर्तें और आरएण्डडी खर्चों की पात्रता और उनकी मात्रा देखने के लिए विशेष रूप से निर्धारण के समय पर निर्धारिती द्वारा दाखिल विवरणी के साथ आरएण्डडी सुविधा के लेखापरीक्षित लेखे के प्रस्तुतीकरण का पालन करे।


मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2015) कि आयकर कार्रवाई के दृष्टिकोण से खर्चों के आवंटन आदि जैसी सूचना एकत्र करने के लिए लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र के वर्तमान प्रपत्र के संशोधन हेतु डीएसआईआर से परामर्श किया जाएगा। मंत्रालय ने आगे बताया (जनवरी 2015) कि दाखिल करने के लिए लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र की ई-समर्थकारी की व्यवहार्यता की आईटीडी द्वारा भी जांच की जाएगी।

नई दिल्ली
दिनांक: 5 मार्च 2015


(मनीष कुमार)
प्रधान निदेशक (प्रत्यक्ष कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 5 मार्च 2015


(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक